Seventeenth Loksabha

>

Title: Regarding request for CBI probe into the alleged irregularities by Managing Director of Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh-laid.

श्री देवेन्द्र सिंह 'भोले' (अकबरपुर): मैं सरकार का ध्यान अपने लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जनपद कानपुर नगर में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के उपक्रम भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम के पूर्व यूपीए सरकार में 21.03.2014 में चयनित वर्तमान प्रबन्ध निदेशक द्वारा अपने पद का कथित रूप से दुरूपयोग करते सरकारी उपकरणों की खरीदफरोख्त में किये गए आर्थिक अनियमितताओं एवं योग्यता न होते हुए भी उच्च पदों पर कथित रूप से नियुक्ति किये जाने की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। महोदय, मेरी लोकसभा क्षेत्र की कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का सबसे बड़ा उपक्रम भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम स्थापित है जहाँ पर दिव्यांग जनों हेतु उपकरणों का निर्माण किया जाता है । उक्त निगम के प्रबन्ध निदेशक के द्वारा उपकरणों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले सामानों की खरीदफरोख्त हेतु की जाने वाली निविदाओं में कथित रूप से अपने पद का दुरूपयोग करते हुए एवं आर्थिक अनियमितताओं में लिप्त होने के चलते एल-1 को वर्क आर्डर न देकर एल-2 से अधिक मूल्यों में सामान की खरीद की गयी जिससे सरकारी धन के नुक्सान के साथ साथ गुणवत्ता विहीन सामान की खरीददारी की गयी सके सभी साक्ष्य मेरे द्वारा उपलब्ध कराये गए इसके अलावा प्रबन्ध निदेशक के द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुए एवं योग्यता न होते हुए भी उपमहाप्रबंधक (मार्केटिंग) जैसे मुख्य पदों के साथ साथ अनेक पदों पर कथित रूप से अपने चहेतों को पदासीन किया गया जिनके प्रमाण भी मेरे द्वारा प्रेषित किये गए| उक्त के अलावा यह भी अवगत कराना है कि वर्तमान प्रबन्ध निदेशक जो कि पूर्व में महाप्रबन्धक नेशनल शीड कार्पोरेशन (एनएससी) में पद पर पदस्थ रहते हुए गलत तथ्यों के आधार पर कथित अवैध रूप से उच्च वेतनमान तथा अनुचित वित्तीय लाभ लिया जाता रहा है उक्त समस्त प्रकरणों के सम्बन्ध में मेरे द्वारा सभी साक्ष्यों सहित माननीय मंत्री एवं सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय एवं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयोग को कई बार पत्रों के माध्यम से एवं स्वयं भेंट कर अवगत कराया गया किन्तु अत्यंत खेद का विषय है कि सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा न तो उक्त प्रकरणों में कोई कार्यवाही और न ही किसी कार्यवाही से मुझे अवगत कराया गया। विलम्ब के चलते प्रबन्ध निदेशक का कार्य काल भी लगातार बढ़ाया जाता रहा है। अतः सरकार से निवेदन है कि भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम के प्रबन्ध निदेशक के द्वारा किये गए कथित कार्यों की सीबीआई जाँच कराये जाने हेतु सम्बंधित को आवश्यक आदेश/निर्देश निर्गत करने की कृपा करें।